



उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

आर०एम०ए० नं०-23/2019-20

बड़ा बाबूलाल राय वगैरह

बनाम

वासुदेव साह वगैरह

-: आदेश :-

दिनांक 10.07.21

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना। अभिलेख में उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया।

वर्तमान अपीलवाद की प्रक्रिया बड़ा बाबूलाल राय पे०-स्व० चोरासी राय वो जमनी देवी पति-छोटा बाबूलाल राय वो अमीन राय वो जलभरी राय वो शंकर राय वो जागेश्वर राय पे०-स्व० भोला राय सभी साकिनान पैरडीह थाना-गोड्डा नगर जिला-गोड्डा के अपील आवेदन के आधार पर प्रारंभ किया गया है। अपीलकर्तागण ने अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के आर०ई०आर० केश नं०-66/2016-17 के आदेश दिनांक-07.08.2019 के विरुद्ध अपील वाद दायर किया है। अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के आर०ई०आर० केश नं०-66/16-17 के आदेश दिनांक-07.08.19 द्वारा अपीलकर्तागण के आवेदन खारिज किया है।

अपीलकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि मौजा पैरडीह नं०-511 जमाबंदी सं०-65 गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में मालो राय के नाम से दर्ज है। अपीलकर्ता बड़ा बाबूलाल राय जमाबंदी रैयत का पोता है एवं अन्य अपीलकर्तागण उनका छर पोता है। उत्तरवादी प्रथम पक्ष बिल्कुल ही बाहरी व्यक्ति है। उनलोगों का उस जमीन पर किसी तरह का कोई हक एवं दावा नहीं है। उत्तरवादी प्रथम पक्ष के द्वारा जबरन अपीलकर्तागण के पैतृक जमीन को कब्जा किया है, जबकि सम्पूर्ण जमाबंदी की जमीन का मालगुजारी रसीद अपीलकर्तागण के द्वारा प्राप्त कर चुके हैं। उनका आगे कथन है कि विद्वान अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के द्वारा मूल आवेदन में दर्शाये गये तथ्यों को सही तरीका से नहीं देखा गया है। क्योंकि अपीलकर्तागण ने अपने मूल आवेदन में उल्लेख किया था कि अपीलकर्तागण के पैतृक जमीन के प्रत्येक दाग नंबर के आधा जमीन को उत्तरवादी प्रथम पक्ष के द्वारा अवैध ढंग से कब्जा किया गया है। इसलिए उत्तरवादी प्रथम पक्ष को उस जमीन से उच्छेद किया जा सकता है। लेकिन निम्न न्यायालय ने उत्तरवादी प्रथम पक्ष को उस जमीन से उच्छेद नहीं किया है। इस प्रकार निम्न न्यायालय का पारित आदेश नियम संगत नहीं है। उन्होंने निम्न

न्यायालय को निरस्त करते हुए निम्न न्यायालय को पुनर्विचार हेतु वापस करने के लिए अनुरोध किया है।

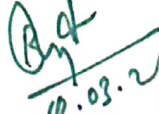
उत्तरवादी प्रथम पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि मौजा पैरडीह नं०-511 जमाबंदी सं०-65 दाग नं०-100, 182, 206, 283/1098, 53, 56, 81, 183, 201, 205, 210, 248, 216, 534, 535 कुल रकवा 13-07-11 धुर जमीन गेंजर सेंटलमेंट पर्चा में मालो राय एवं साहेब राय पे०-मेघु राय के नाम से दर्ज है। जमाबंदी रैयत के द्वारा उक्त जमाबंदी की जमीन का मालगुजारी नहीं चुकाने के कारण संधाल परगना मेनुअल 1911 के प्रावधानानुसार मूल रैयतों के विरुद्ध सरकार की ओर से आई०आर०ई० केश नं०-138/31-32 श्रीमान् अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के न्यायालय में प्रारंभ हुआ। उक्त वाद के आदेशानुसार अपीलकर्तागण के पूर्वजों ने मालगुजारी नहीं चुकाया था। इसलिए अपीलकर्तागण के पूर्वजों को उक्त जमीन से उच्छेद किया गया। उत्तरवादी प्रथम पक्ष के द्वारा मालगुजारी का राशि चुकायी गयी। इसलिए उत्तरवादीगण के पूर्वजों के साथ उक्त जमाबंदी की कुल रकवा में से रकवा 06-12-07 धुर जमीन बंदोवस्त की गयी। उक्त बंदोवस्त जमीन पर न्यायालय के आदेशानुसार दखल दिहानी भी दिलाया गया। अंचल अधिकारी, गोड्डा के नामांतरण वाद सं०-159/60 के द्वारा उत्तरवादीगण के पूर्वजों के नाम से उक्त जमीन का नामांतरण भी हो गया है। उत्तरवादीगण के पूर्वजों की मृत्यु के बाद उक्त जमीन पर उत्तरवादीगण हकदार एवं दखलकार हुए तथा मालगुजारी चुका कर रसीदें हासिल करते आ रहे हैं। वर्तमान सर्वे सेंटलमेंट पर्चा में भी उत्तरवादीगण का नाम दर्ज है। इस प्रकार अपीलकर्तागण का उक्त जमीन पर कोई हक या दखल नहीं रह गया है। उनका आगे कथन है कि उक्त जमीन के सम्बंध में अपीलकर्तागण की ओर से उत्तरवादीगण के विरुद्ध सबजज, गोड्डा के न्यायालय में टा०सूट नं०-84/95 भी दायर किया गया था, जिसमें उत्तरवादीगण के पक्ष में निर्णय दिया गया था तथा अपीलकर्तागण के आवेदन को खारिज किया गया था। उक्त टा०सूट के निर्णय के विरुद्ध अपीलकर्तागण की ओर से मान्नीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गोड्डा के न्यायालय में अपील दायर किया गया था, जो टा०अपील नं०-08/2005 दर्ज किया गया। उसे मान्नीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गोड्डा ने सुनवाई के पश्चात दिनांक-01.03.2006 को खारिज कर दिया। उनका आगे कथन है कि अपीलकर्तागण की ओर से उत्तरवादीगण पर उक्त जमीन से फसल लुटने का क्रिमिनल केश भी किया गया था, जो श्री डी०एन००पाण्डेय न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी गोड्डा के न्यायालय में टी०आर०नं०-305/97 कह कर ट्रायल हुआ। जिसमें न्यायालय ने उत्तरवादीगण को निर्दोष साबित कर रिहा कर दिया गया। इसके अलावे अपीलकर्तागण की ओर से उक्त जमीन से बेदखल करने के लिए कई झूठा फौजदारी मुकदमा दर्ज किया गया था। सभी मुकदमा में उत्तरवादी को

न्यायालय द्वारा बरी किया गया तथा अपीलकर्तागण के केश को खारिज किया गया। उनका आगे कथन है कि उत्तरवादीगण के पूर्वज उक्त जमीन पर सक्षम पदाधिकारी के आदेशानुसार न्यायालय द्वारा सन्थाल परगना मेनुअल 1911 के अनुसार विधिवत बंदोवस्त लेकर दखलकार हुए हैं। उनके मृत्यु उपरांत प्रथम श्रेणी उत्तराधिकारी के हैसियत से उत्तरवादीगण उक्त जमीन पर दखलकार हुए एवं शांतिपूर्ण ढंग से जोत आबाद कर रहे हैं। इसलिए उक्त जमीन से उत्तरवादीगण को उच्छेद करने का प्रश्न ही नहीं उठता है। अपीलकर्तागण की ओर से दायर अपीलवाद निराधार एवं अनावश्यक होने के कारण खारिज करने योग्य है। उन्होंने निम्न न्यायालय के आदेश को बरकरार रखते हुए अपीलकर्तागण के अपील आवेदन को खारिज करने के लिए अनुरोध किया है।

उपरोक्त तथ्यों अभिलेखबद्ध कागजात एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मौजा पैरडीह नं०-511, जमाबंदी सं०-65 रकवा 13-07-11 धूर जमीन गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में मालो राय वो साहेब राय वल्द मेघु राय कौम घटवाल सा०-देह के नाम दर्ज है। निम्न न्यायालय के आदेश से यह स्पष्ट होता है कि उक्त जमाबंदी का मालगुजारी राशि बकाया होने एवं उस बकाया राशि का भुगतान नहीं करने के कारण आर०ई०आर० केश नं०-138/31-32 के द्वारा अपीलकर्तागण के पूर्वज को उच्छेद किया गया था तथा प्रयाग मंडल एवं किसुन मंडल के द्वारा बकाया मालगुजारी राशि भुगतान करने के कारण आदेश दिनांक-07.02.1934 के द्वारा उक्त जमाबंदी के रकवा 06-12-07 धूर जमीन की बंदोवस्ती की गयी है तथा आदेश दिनांक-18.07.1934 के द्वारा दखल दिहानी भी दिलाया गया। इससे उत्तरवादीगण का उक्त जमीन पर दखल अवैध प्रतीत नहीं होता है। साथ ही अपीलकर्तागण की ओर से निम्न न्यायालय से भिन्न कोई अलग तथ्य या कागजात भी प्रस्तुत नहीं किया है। ऐसी स्थिति में निम्न न्यायालय का पारित आदेश नियम के विपरीत प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के आर०ई०आर० केश नं०-66/16-17 में आदेश दिनांक-07.08.2019 को बरकरार रखते हुए अपीलकर्तागण के अपील आवेदन को खारिज किया जाता है।

लिखाया एवं शुद्ध किया।


उपायुक्त,
गोड्डा।


10.03.24
उपायुक्त,
गोड्डा।